

खबर संक्षेप



24 सप्ताह तक के गर्भपात को रिवर्स ट्रेक करें एसीएमओ : एसीएमओ चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह शर्मा के निर्देशानुसार हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक आज यहाँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसीएमओ के सीएमओ को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक किए गए गर्भपात की रिवर्स ट्रेकिंग शुरू करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य एसी प्रक्रियाओं में शामिल चिकित्सकों की पहचान करना तथा उल्लेखन के मामलों में सख्त कार्रवाई शुरू करना है। रिवर्स ट्रेकिंग के लिए एक व्यापक प्रक्रिया पहले ही सभी सीएमओ के साथ साझा की जा चुकी है। हरियाणा का लिंगानुपात इस वर्ष 7 जुलाई तक सुधारकर 904 हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 903 था। बैठक में यह भी बताया गया कि अवेध मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई के कारण राज्य भर में लगभग 500 ऐसे केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इसके कारण पिछले दो महीनों में वैध एमटीपी में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है।

मंत्री को मलाईदार पदों पर पोस्टिंग करनी पड़ा महंगा

विज ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, परिवहन और ऊर्जा विभाग में करप्शन, तुरंत जांच करवाओ

- अनिल विज के पत्र से दगियों के उड़े होश
- भ्रष्टाचार की बू आने के बाद उठायी कदम

हरिभूमि ब्यूरो चंडीगढ़

हरियाणा के परिवहन और ऊर्जा, श्रम मंत्री ने अब अपने परिवहन और ऊर्जा विभाग के कुछ अहम पदों पर बैठने के लिए बड़े बड़े लोगों की सिफारिश कराना इस तरह के लोगों के गले की फांस बनने जा रहा है। अब विज ने सारे माजूर और भ्रष्टाचार की बू आने के बाद में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर (सीएम फ्लाइंग) को मामला सौंपकर जांच के लिए कहा है। विज ने मीडिया के पूछे जाने पर पत्र भेजने की बात स्वीकार की है। उन्होंने सीएम फ्लाइंग को जांच के लिए पत्र भेजकर आए दिन सीईआई और एमवीआई जैसे पदों पर ट्रांसफर के लिए आ रही थी सिफारिशों का जिक्र किया है। इन पदों पर बड़ी संख्या में मारामारी के मामले को समझते हुए उन्होंने इस तरह की सीटों पर शिकंजा कसने के लिए कदम उठा दिया है। अब मंत्री विज द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद में दागी कर्मियों और माल

ऊर्जा विभाग में सीईआई और परिवहन में एमवीआई पदों पर बैठने के लिए कर्मचारी लगा रहे रसूखदारों का जुगाड़

एमवीआई वाहन सुरक्षा प्रमाण पत्र देने का काम करता है



आरटीए ऑफिस एमवीआई अर्थात मोटर व्हीकल इस्पेक्टर वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने का जिम्मा होता है। सुरक्षा और प्रवृक्षण मानकों की जांच का जिम्मा, यह अधिकारी सुनिश्चित होता है। इसमें ही बड़ा खेल होता है, हर गाड़ी की पंजिंग उसकी फिटनेस तमाम बातों को चेक किया जाता है। बताते हैं कि खराब गाड़ियों को पंजिंग, कमरिथल वाहनों को फिटनेस देने में अस्वी खासी सेवा होती है, इसलिए बड़ा खेल इस पोस्ट के लिए चलता है।

सीईआई बड़े संस्थानों में सुरक्षा मानकों को देखता है



हरियाणा में चीफ इलेक्ट्रिकल इस्पेक्टर का काम अहम होता है। बड़े संस्थानों में निरीक्षण के लिए जाने वाले इन अफसरों के आगे पीछे लोग घूमते हैं, सुरक्षा मानकों की जांच पड़ताल करने वाले इस पोस्ट के अधिकारी को भी ऊपरी आया होती है। हादसे और इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन में लापरवाही और खतरा नहीं हो ताकि जान माल को रखा हो सके, इस बात को सुनिश्चित करना होता है, लेकिन ठीक तरह से पड़ताल के स्थान पर बस खानापूर्ती ही की जाती है।

कमाने वाले अफसरों में हड़कंप मच गया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने दरअसल, जो पत्र लिखा है, उसमें ऊर्जा विभाग (बिजली महकमे) में चीफ इलेक्ट्रिकल

इस्पेक्टर (सीईआई) और परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल इस्पेक्टर (एमवीआई) पदों को लेकर जांच के लिए सीएम फ्लाइंग को पत्र लिख दिया है। बताया गया है कि मंत्री विज को उनके सूत्रों ने

विज बोले

अपने विभाग में गोलमाल नहीं चलने दूंगा

ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिस वक्त से उनके पास ऊर्जा और परिवहन विभाग आए हैं, तब से रोजाना उनके पास ऊर्जा विभाग में चीफ इलेक्ट्रिकल इस्पेक्टर और परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल इस्पेक्टर के पदों पर लगाने के लिए काफी सिफारिशें लगातार आ रही हैं। लोगों की अपील होती है कि परिवहन विभाग में एमवीआई में लागा दो और बिजली विभाग में चीफ इलेक्ट्रिकल इस्पेक्टर लागा दो। इतना ही नहीं यह लोग मंत्री विज पर दबाव भी डालते हैं, साथ ही काम नहीं बनने पर वे प्रभावशाली लोगों, विज के करीबियों को झोलाबल कर मदद की मांग करते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए विज ने पूरे प्रदेश में इस तरह की पोस्ट पर बैठे अधिकारियों, कर्मियों को लेकर जांच करने के लिए कहा है।



एसवाईएल पर दोनों राज्यों के बीच दिल्ली में मंथन आज, सैनी और मान ने की तैयारी

बैठक में अपना-अपना पक्ष रखेंगे हरियाणा और पंजाब

योगेश शर्मा चंडीगढ़

आखिरकार एक बार फिर से पांच दशक पुराने सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) पर विवाद पर सुप्रीम अदालत के निर्देशों पर बुधवार को अहम बैठक पंजाब और हरियाणा के बीच होने जा रही है। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के आला अफसर और प्रमुख चेहरे आमने-सामने होंगे। केंद्र की मध्यस्थता में नौ जुलाई को मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान और मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी एसवाईएल के मुद्दे पर राज्यों की ओर से पक्ष रखेंगे।

नहर पर वार्ता से पहले अफसरों से की चर्चा



हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) को लेकर आला अफसरों के साथ में अहम बैठक कर ली है। बुधवार को होने वाली बैठक को लेकर नायब सैनी के चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर बैठक की गई। इस दौरान संबंधित विभागों के अफसर मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को कंट्रोवर्सी से जुड़े सभी फैक्ट्स पर व्यापक तैयारी रखने और काम करने निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा इस बैठक में मजबूती से अपना-अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों सौंपने में अधिकारियों को संबंधित दस्तावेजों अब तक हूई मीटिंगों का ब्योरा तैयार थे, जिस पर अधिकारियों ने अपडेट भी दिया है।

कर चुके हैं कि पंजाब के पास किसी भी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। दावा है कि राज्य में 153 में से 115 ब्लॉक डार्क जोन में हैं और जहां भीजल स्तर 400 से 600 फुट नीचे चला है। मान कई बार सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि यमुना का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, जो हरियाणा से यूपी से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जा रहा है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले

एसवाईएल पर मीटिंग करने के बजाय अवमानना का केस दायर करे भाजपा

चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसवाईएल को लेकर होने वाली प्रस्तावित बैठक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब इन बैठकों के दौर से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबे टाइम पहले हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाने की जिम्मेदारी कोर्ट ने केंद्र सरकार को सौंपी थी। हरियाणा और केंद्र दोनों जगह, बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अब तक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा के हरियाणा विरोधी रवैये के चलते यह नहीं हो पाया। अब अगर सरकार इसके बारे में बात कर रही है तो उसे सीधे कंटेन्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर करना चाहिए।

अर्जुन चौदाला ने कहा

एसवाईएल को लेकर हो रही बैठक के दौरान होश में आए भगवंत मान



चंडीगढ़। एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बुधवार को केंद्रीय मंत्री के साथ होने वाली बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए इनेलो विधायक अर्जुन चौदाला ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक में होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री मान जो कहते हैं कि यह पंजाब का पानी है किसी को नहीं देंगे, वो कौन से कुएं से एसवाईएल का पानी खोद कर लाए हैं। एसवाईएल का पानी तो सियाचिन ग्लेशियर से आता है, तो यह पंजाब का पानी कैसे हुआ। सतलुज यमुना लिंक विवाद पर केंद्र की मध्यस्थता में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच बुधवार को दिल्ली होगी बातचीत।

लाखों कर्मचारी और मजदूर आज हड़ताल पर

चंडीगढ़। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संघों की फेडरेशनों के आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर 9 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे। राज्य में इस हड़ताल का आह्वान प्रमुख कर्मचारी संगठन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व हरियाणा कर्मचारी महासंघ और मजदूर संगठन सीटू, एटक, एचएमएस, एआईयूटीयूसी तथा इनसे संबंधित सैकड़ों कर्मचारी एवं मजदूर संगठनों ने संयुक्त रूप से किया है। हड़ताल के कारण शहरी

स्थानीय निकाय, बिजली, रोडवेज, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी वीएडआर, स्वास्थ्य, वन, टूरिज्म, शिक्षा, रिवेन्यू, महिला एवं बाल विकास, एचएसवीपी आदि विभागों में कामकाज प्रभावित रहने की प्रबल संभावना है। आंगनबाड़ी, आशा व मिड डे मील वर्कर्स सहित ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी बड़ी संख्या में हड़ताल पर रहेंगे। मजदूर संगठन सीटू, एटक, एचएमएस व एआईयूटीयूसी से जुड़े फरीदाबाद, गुरुग्राम, धारूहेड़ा, मानेसर, बावल,

सोनीपत, पानीपत, हिसार में प्राइवेट कारखानों में काम करने वाले औद्योगिक मजदूर हड़ताल में शामिल होने की संभावना है। बैंकों, इंश्योरेंस, जरनल इंश्योरेंस, पोस्टल, दूरसंचार आदि केंद्र सरकार के कई अन्य विभागों में भी हड़ताल रहेगी। कर्मचारी और मजदूर हड़ताल करेंगे और अपने अपने कार्यस्थलों पर केंद्र एवं राज्य सरकार की मजदूर एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ और प्रदर्शन करेंगे इसके बाद हड़ताली मजदूर व कर्मचारी जुलूस निकालेंगे।

हरियाणा सरकार निविदा सूचना

क्र. सं.	निविदा संख्या	कार्य का विवरण	निविदा खुलने की तिथि	अनुमानित लागत	बिडिंग शुरू होने की तिथि	कार्य पूरा करने की अवधि
1	01-जीएस-ई-बी-अंबाला/2025-26	अंबाला मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के सॉफ्ट अपग्रेडेशन / सुधार के लिए कला एवं संस्कृति के कार्य प्रायोजन।	07.07.2025	₹. 98,40,00/-	15.07.2025	29.07.2025

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें: www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in
संवाद-13/2026/40/36371/1/88/6 दि. 08.07.25

हरियाणा सरकार निविदा सूचना

क्र. सं.	निविदा संख्या	कार्य का विवरण	निविदा खुलने की तिथि	अनुमानित लागत	बिडिंग शुरू होने की तिथि	कार्य पूरा करने की अवधि
1	डीएचबीओ/2025-26	पुनर्गठनीय सं. आरएएसएम 06/पीडी एंड सी/2025-26 के तहत ई-निविदा के माध्यम से 2.25 एमएमबी क्षमता के थ्री कनेक्टेड ग्राउंड मॉडरेट लोडर प्लांट के 5 वन हेतु व्यापक डो एवं स्प और दूरस्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आरएएसएम तथा लोडर प्लांट से सम्बंधित 33 केबी अथवा 11 केबी लोडन को डिजाइन इंजीनियरिंग अधिष्ठाता और आपूर्ति निर्माण एवं स्थानांतरण प्रदान।	07.07.2025	₹. 11,40,00,00/-	14.07.2025	11.04.2026
2	डीएचबीओ/2025-26	पुनर्गठनीय सं. आरएएसएम 06/पीडी एंड सी/2025-26 के तहत ई-निविदा के माध्यम से 2.25 एमएमबी क्षमता के थ्री कनेक्टेड ग्राउंड मॉडरेट लोडर प्लांट के 5 वन हेतु व्यापक डो एवं स्प और दूरस्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आरएएसएम तथा लोडर प्लांट से सम्बंधित 33 केबी अथवा 11 केबी लोडन को डिजाइन इंजीनियरिंग अधिष्ठाता और आपूर्ति निर्माण एवं स्थानांतरण प्रदान।	07.07.2025	₹. 11,40,00,00/-	14.07.2025	11.04.2026
3	डीएचबीओ/2025-26	पुनर्गठनीय सं. आरएएसएम 06/पीडी एंड सी/2025-26 के तहत ई-निविदा के माध्यम से 2.25 एमएमबी क्षमता के थ्री कनेक्टेड ग्राउंड मॉडरेट लोडर प्लांट के 5 वन हेतु व्यापक डो एवं स्प और दूरस्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आरएएसएम तथा लोडर प्लांट से सम्बंधित 33 केबी अथवा 11 केबी लोडन को डिजाइन इंजीनियरिंग अधिष्ठाता और आपूर्ति निर्माण एवं स्थानांतरण प्रदान।	07.07.2025	₹. 11,40,00,00/-	14.07.2025	11.04.2026

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें: www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in
संवाद-13/2026/60/36356/1/88/6 दि. 08.07.25

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL, KAITHAL
NEAR GOVT. BOY SCHOOL, KAITHAL -136027
E-MAIL: eo-kaithal@ulbharyana.gov.in

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के रूप में विशेष अपील (सी) संख्या 8519/2006 में पारित दिनांक 29.09.2009 के आदेश के तहत निर्देश दिया कि उस तिथि के बाद सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर मन्दिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के नाम वा कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रारंभिक रूप से रिपोर्ट मांगने और कार्यान्वयन की निगरानी के बाद दिनांक 31.01.2018 के आदेश के तहत मामलों को प्रभावी तरीके से अपने आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबन्धित उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है। उच्च आदेशों के पालन में सरकारी भूमि, ग्रीन बेल्ट, सरकारी पार्क, सड़क, फुटपाथ इत्यादि पर बने अवैध धार्मिक संस्थान, स्टूफर, भवन आदि को तुरंत प्रभाव से हटा लें अन्यथा सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त भवनों को तोड़-फोड़ कर हटा दिया जाएगा, जिसमें होने वाला हर्जा खर्चा के लिए उपरोक्त संस्थानों को चलाने वाले अनुयायी स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके अतिरिक्त संबन्धित के विरुद्ध दंडात्मक एवं न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

विस अध्यक्ष कल्याण ने निकाय सम्मेलन में बेहतर काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द कल्याण ने मंगलवार को गुरुग्राम के मानेसर स्थित आईकेट में 3-4 जुलाई को हुए राष्ट्रीय निकाय सम्मेलन में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले नोडल अधिकारियों व कर्मचारियों की विधानसभा के समिति कक्ष में बैठक ली। उन्होंने राष्ट्रीय निकाय सम्मेलन की विशेष सफलता के लिए विधानसभा के सभी संबंधित कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन की कामयाबी से हरियाणा विधानसभा का कद दूर दराज के इलाकों में बढ़ा है और वे हम सब के लिए गर्व की बात है।

उत्तर रेलवे ई-निविदा सूचना

क्र. सं.	निविदा संख्या	कार्य का विवरण	निविदा खुलने की तिथि	अनुमानित लागत	बिडिंग शुरू होने की तिथि	कार्य पूरा करने की अवधि
1	01-जीएस-ई-बी-अंबाला/2025-26	अंबाला मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के सॉफ्ट अपग्रेडेशन / सुधार के लिए कला एवं संस्कृति के कार्य प्रायोजन।	07.07.2025	₹. 98,40,00/-	15.07.2025	29.07.2025

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें: www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in
संवाद-13/2026/40/36371/1/88/6 दि. 08.07.25

कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय सोनीपत

मु.न. 258 दिनांक 27.06.2025 धारा 140 (3) बी.एन.एस. धाना सीटी गोहाना जिला सोनीपत।
पता निजामपुर मानेसर हाल गली न.3 हरफुल कालोनी गोहाना सोनीपत।
उम-15 वर्ष
कद-5 फुट।
हुलिया- रंग सांवला, लम्बवरा चेहरा, काले बाल, काली आंखें, लम्बी नाक है।
पहननावा - काले रंग की जून्स, लाल रंग की फुल बाजु टी-शर्ट पहना है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25-06-2025 को अंशु पुत्र सुंदर वासी निजामपुर मानेसर हाल गली न.3 हरफुल कालोनी गोहाना सोनीपत हरियाणा जो बिना किसी को बताए अपने घर से कहीं चला गया है। जो अब तक वापिस नहीं आया है। जिस सम्बंध में मुकदमा उपरोक्त दर्ज रजिस्टर है। अगर उपरोक्त गुमशुदगी बारे किसी व्यक्ति को कोई सूचना मिले तो निम्नलिखित नम्बरों पर सूचित करें।
प्रबन्धक धाना- 7419410544
अनुसंधान कर्ता मो 708295339100
कन्ट्रोल रूम सोनीपत- 0130-2222903,100
हस्ता/-अपरधक अभिलेख अधिकारी, कृते पुलिस आयुक्त। मुख्यालय, सोनीपत

पीआरडीएच-1084/11/3617/2026/36384/88/6 दि. 08.07.2025

नोटिस (ई-ऑक्शन)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय जेल-1, हिसार के बन्दियों के भोजन के पश्चात बची हुई रोटियाँ, दाल सब्जी व खानस/पलोथन का आटा को सप्ताह में दो बार उठाने हेतु दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2026 तक के लिए केन्द्रीय जेल-1, हिसार के कार्यालय द्वारा दिनांक 15.07.2026 को सुबह 9:00 बजे से सांय 04:30 बजे तक ऑनलाईन ऑक्शन करवाई जाएगी। कोई भी इच्छुक ठेकेदार ऑनलाईन ऑक्शन में भाग ले सकता है।
ठेकेदार को सूचित किया जाता है:-
1. स्वीकृत ठेकेदार को 10,000 ₹ बतौर धरोहर राशि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। और ऑनलाईन ऑक्शन हेतु ठेकेदार को DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्लास तीन की जरूरत होगी। तथा ठेकेदार को <https://eauction.gov.in> पर साईन-अप करना होगा।
2. स्वीकृत ठेकेदार को बची हुई रोटियों व दाल सब्जी सप्ताह में दो बार जरूर उठानी होंगी।
3. स्वीकृत ठेकेदार को अवधि दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2026 तक या सरकार जब तक उचित समझे के समय के लिए होगी।
4. यदि स्वीकृत ठेकेदार उपरोक्त शर्तों को तोड़ता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त करके ठेके को समाप्त कर दिया जाएगा।
5. अधीक्षक जेल को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए किसी भी ऑक्शन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।
6. इस कार्य में उत्पन्न किसी प्रकार के झगड़े या व्यवधान का निपटारा स्थानीय न्यायालय में होगा।
7. ठेकेदार जेल के अन्दर किसी भी बन्दियों से किसी प्रकार का लेनदेन या व्यवहार नहीं करेगा और ना ही किसी प्रकार का ऐसा कार्य करेगा जो जेल नियमों के विरुद्ध हो। ऐसा करने पर उसे नियमों के अनुसार दण्डित किया जा सकता है।
8. अन्य शर्तें मौके पर सुना दी जाएगी।
हस्ता/-अधीक्षक जेल केन्द्रीय जेल, हिसार।
पीआरडीएच 1277/11/94/2026/36366/88/6 दि. 08/07/2025

MUNICIPAL COMMITTEE, PUNDRI
OPP: C.I.S.K.M.V. COLLEGE, MAIN ROAD, PUNDRI-136026
E-MAIL: secretarympundri01@gmail.com, Ph. 01746-270273

सार्वजनिक सूचना

“सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के रूप में विशेष अपील (सी) संख्या 8519/2006 में पारित दिनांक 29.09.2009 के आदेश के तहत निर्देश दिया कि उस तिथि के बाद सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक पार्कों या सार्वजनिक स्थानों आदि पर मन्दिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रारंभिक रूप से रिपोर्ट मांगने और कार्यान्वयन की निगरानी के बाद दिनांक 31.01.2018 के आदेश के तहत मामलों को प्रभावी तरीके से अपने आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित उच्च न्यायालय को भेज दिया है। उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन में सरकारी भूमि, ग्रीन बेल्ट, सरकारी पार्कों, सड़क, फुटपाथ, इत्यादि पर बने अवैध संस्थान स्टूफर, भवन आदि को तुरंत प्रभाव से हटा लें अन्यथा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त भवनों को तोड़-फोड़ कर हटा दिया जाएगा। जिसमें होने वाले हर्जा खर्चा के लिए उपरोक्त संस्थानों को चलाने वाले अनुयायी स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके अतिरिक्त संबन्धित के विरुद्ध दंडात्मक एवं न्यायालय के आदेशों की अवमानना की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।”
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

बांग्लादेश, थाइलैंड सहित एक दर्जन पर लगा उच्च शुल्क अमेरिका के कदम से भारत को कपड़ा 'फुटिवर' क्षेत्रों में होगा लाभ : निर्यातक

एजेंसी ► नई दिल्ली

बांग्लादेश और थाइलैंड सहित एक दर्जन से अधिक देशों पर उच्च शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले के बाद भारत के परिधान और 'फुटिवर' जैसे निर्यात क्षेत्रों को वहां के बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ मिलने की उम्मीद है। निर्यातकों ने यह बात कही।

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को जापान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीशिया पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। वहीं दक्षिण अफ्रीका, बोस्निया-हर्जोगोविना पर 30 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत, बांग्लादेश, सर्बिया पर 35 प्रतिशत, कम्बोडिया, थाइलैंड पर 36 प्रतिशत और लाओस और म्यांमा पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाने का ऐलान किया। ये शुल्क एक अगस्त से लागू होंगे।

खास बातें

- अमेरिका को परिधान निर्यात करने वाला बांग्लादेश तीसरा बड़ा देश
- परिधान क्षेत्र में भारत का अमेरिका को 2.5 अरब डॉलर का था निर्यात



भारत के रबड़ के निर्यात में ही हो सकेगी वृद्धि

निर्यातकों के शीर्ष निर्यात फिचो (फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन) के अध्यक्ष एस सी रत्नन ने कहा कि चमड़ा और परिधान जैसे क्षेत्रों को भारत के प्रतिस्पर्धी देशों से प्रतिस्पर्धी लाभ मिल सकता है। मुंबई के एक निर्यातक ने कहा कि थाइलैंड पर बड़े हुए शुल्क से रबड़ और उसके उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है।

हमें चमड़ा क्षेत्र में लाभ मिलेगा

थाइलैंड, अमेरिका को रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक है। उसकी हिस्सेदारी 15.16 प्रतिशत है, जबकि भारत 2.93 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर है। निर्यातक ने कहा, "हमें चमड़ा क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा।"

बांग्लादेश की बाजार हिस्सेदारी 13.15 फीसदी

बांग्लादेश 2024 में 13.15 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ अमेरिका को परिधान (बिना बुना हुआ) का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र में भारत का अमेरिका को निर्यात 2.5 अरब डॉलर था। लेकिन भारत शीर्ष तीन देशों में नहीं है।

कम्बोडिया भी परिधान निर्यात में भारत से आगे

बुने हुए परिधानों में कम्बोडिया की हिस्सेदारी करीब छह प्रतिशत है और वह भारत (5.09 प्रतिशत) से आगे है। एक निर्यातक ने कहा, "अमेरिकी परिधान बाजार में भारत को बांग्लादेश और वियतनाम से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश पर उच्च शुल्क से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।"

समझौते को अंतिम रूप देने में सावधानी से आगे बढ़े भारत : जीटीआरआई

आर्थिक शोध संस्थान जैटि सीटीआरआई ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के समय भारत को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्वीस्टिगटिव (जीटीआरआई)' ने कहा, "अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 'गॉडाल' मुक्त व्यापार समझौते का नहीं बल्कि अमेरिकी जवाबी शुल्क के सामने झुकने का है।"

सोना बढ़कर 99,120 रुपए प्रति दस ग्राम

एजेंसी ► नई दिल्ली

स्टॉकस्टों की ताजा लिवाली के कारण मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने की कीमत 550 रुपये बढ़कर 99,120 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सराफा संघ ने यह जानकारी दी है। सोमवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 98,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

सराफा संघ ने बताया कि 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 500 रुपये बढ़कर 98,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। इसके अलावा, चांदी की कीमतें मंगलवार को लगातार तीसरे सत्र में भी

फास्टेग से टोल संग्रह पहली तिमाही में 19.6 प्रतिशत बढ़कर 20,682 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईसीटी) के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में फास्टेग के जरिये राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह 19.6 प्रतिशत बढ़कर 20,682.87 करोड़ रुपये हो गया। एनईसीटी के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही में टोल उपयोगकर्ताओं की संख्या भी 16.2 प्रतिशत बढ़कर 117.3 करोड़ हो गई। एक साल पहले की इसी अवधि में यह 100.98 करोड़ थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एक अप्रैल, 2025 से देशभर के राजमार्गों पर टोल शुल्क में औसतन 4-5 प्रतिशत की वृद्धि की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गिरीश कार्दकर ने हाल में कहा था कि सरकार 15 अगस्त से निजी महलों के लिए 3,000 रुपये की कीमत वाला फास्टेग-आधारित वार्षिक पास पेश करेगी।



सोना 550 रुपए चढ़ा और चांदी रही स्थिर

1,04,800 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर अतिरिक्त रही। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 11.42 डॉलर या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,325.09 डॉलर प्रति औंस रह गया। एचडीएफसी सिक्नोरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक - कमोडिटीज, सोमिल गांधी ने कहा, व्यापार युद्ध के फिर से शुरू होने की आशंका बढ़ने के कारण सोने ने कल के नुकसान को उलट दिया और मंगलवार को बढ़त दर्ज की गई।

साइप्रस की कंपनियां भारतीय पोत परिवहन क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी

नई दिल्ली (भाषा)। साइप्रस की कंपनियों इंटरऑरिएंट नेविगेशन कंपनी लिमिटेड और डैनशिप एंड पार्टनर्स लिमिटेड ने भारतीय पोत परिवहन क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। इंटरऑरिएंट ने बयान में कहा कि यह निवेश भारतीय पोत परिवहन क्षेत्र में अत्यंत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) है। इस क्षेत्र को 2005 में 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खोला गया था। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 15 जून, 2025 को साइप्रस यात्रा के कुछ दिन बाद की गई है। मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलीडिस के साथ औपचारिक धार्मिक की थी। बयान के अनुसार, इस निवेश के तहत उसी जहाज भारतीय ध्वज के तहत पंजीकृत होंगे। इंटरऑरिएंट की स्थापना 1979 में हुई थी और यह 100 से अधिक जहाज के बेड़े का प्रबंधन करती है।

COURT NOTICE (U/o 5 Rule 20 CPC) IN THE COURT OF Sh. Jitesh Kumar Sharma, Civil Judge (Junior Division), Jhajjar

Gaurav Kumar alias Sonu son of Suren-der Singh son of Bishan Swaroop Vs. Tahshidar Beri CNR No. HRRJ02-000768-2025 Next Date: -03-09-2025

PUBLICATION ISSUED TO: General Public - India

In above titled case, the defendant(s) respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 03-09-2025 at 10:00 a.m.

For details login to https://highcourtchd.gov.in/?mod=distrcnt_notice&distrcnt=Jhajjar

Sd/- Jitesh Kumar Sharma, Civil Judge (Junior Division), Jhajjar Dated, this day of 07-07-2025

बैंक, आईटी शेयरों में खरीदी से सेंसेक्स 270 अंक चढ़ा

एजेंसी ► मुंबई

स्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 270 अंक के लाभ में रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 25,500 अंक के ऊपर बंद हुआ। एशिया के अन्य बाजारों में मजबूत रुख के साथ बैंक तथा चुनिंदा आईटी शेयरों में लिवाली से बाजार में मजबूती आई। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 270.01 अंक यानी 0.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,712.51 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के तीस शेयरों में 18 लाभ में जबकि 12 नुकसान में रहे। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 61.20 अंक यानी 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,522.50 अंक पर बंद हुआ।

विशेषज्ञों के अनुसार, शेयर बाजार लगभग पूरे कारोबार के दौरान सीमित दायरे में रहा। कारोबार समाप्त होने से पहले कुछ शेयरों में लिवाली हुई। निवेशकों को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में दोसा प्रगति का इंतजार है। इस बीच, अमेरिका ने जवाबी शुल्क लगाने की समयसीमा बढ़ाकर एक अगस्त कर दी है। सेंसेक्स की कंपनियों में कोटक महिंद्रा बैंक, इंटर्नल (पूर्व में जोमैटो), एशियन पेट्स, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि., अदाणी पोर्ट्स, इन्फोसिस और भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे।

चीनी पेशेवरों की वापसी से आईफोन 17 के उत्पादन पर कोई असर नहीं

एजेंसी ► नई दिल्ली

एप्पल वेंडर के संयंत्र से चीनी प्रौद्योगिकी पेशेवरों की वापसी से आगामी आईफोन-17 के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार, भारत में एप्पल के वेंडर फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी चीन से पंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति में ढील का अनुभव किया है। ये वस्तुएं आईफोन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। आईफोन विनिर्माण के घटनाक्रम से अवगत एक सूत्र ने बताया, "फॉक्सकॉन से चीनी पेशेवरों की वापसी से आईफोन के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारत में आईफोन-17 का उत्पादन तय समय के अनुसार होगा।" इस मामले पर एप्पल, फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजे गए सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। कई सूत्रों ने बताया कि फॉक्सकॉन इंडिया के संयंत्रों में काम करने वाले सैकड़ों चीनी पेशेवर पिछले दो माह में चीन लौट गए हैं। उन्होंने बताया कि ये इंजीनियर निर्माण श्रृंखला और कारखाना डिजाइन को संभाल रहे थे।

रुपया 26 पैसे की बढ़त के साथ 85.68 प्रति डॉलर

मुंबई। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर के कमजोर होने के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे बढ़कर 85.68 (अस्थायी) पर बंद हुआ।

मार्केट न्यूज

हीर एक्सप्रेस का नया गाना 'डोरे डोरे दिल पे तेरे' हुआ रिलीज

मुंबई। जब मस्ती भरें बोल, डील की धूप और थार की नोकझोंक मिलें, तो बनता है एक ऐसा गाना जो दिलों में गुंजा नएक, नमसूद किया जाता है। 'हीर एक्सप्रेस' का नया डॉक्यूमेंटरी 'डोरे डोरे दिल पे तेरे', 8 जुलाई को जी म्यूजिक कंफर्मेंस में जरिए रिलीज हो चुका है, और ये अभी से ही दर्शकों की चर्चा में अपनी जगह बना चुका है। इस गाने की खास बात है इसकी चुलबुली रोमांटिक कैमिस्ट्री - जहां एक ओर लड़का थार से मनाने की कोशिश करता है, वहीं लड़की हँसी-ठिठोली में बाधा खा रही है। यही मासुमिल और मस्ती इसे बारी-बारी से अलग बनाती है।

रायल बर्कशायर (यूके) लिमिटेड इन पार्टनर में शामिल हुए हैं इस गाने की हर फ्रेम में मोबाइल स्टूडियो और देसी दिल की अलक मिलती है। गाने में है डील की सीट, पलटते बूढ़ी लैन्डिंग, और एक ऐसी मॉडर्न कैमिस्ट्री - लारिक है। उनका हर एक्सप्रेशन, हर डांस स्टेप और हर किरदार ने खुल कर आता है, जैसे दो युवक नहीं, उस पल को जी रही हैं।

उनके साथ प्रीत कपानी की चुलबुली पहले से भी ज्यादा सजी हुई और चोखल चरन आता है। साथ ही, चार्लेट डेविल और लेटेन बॉय जैसे विटिड कलाकारों की निपटूरी इस गाने को एक इंटरनेशनल अपील देती है।

गाने की कोरियोग्राफी की डिग्निटारी संभाली है अद्वितीय शैली ने - जिन्होंने अपने सिनेमैटिक स्टूडियो का दिल और यूरोपियन धार्मिक बुद्धसूली से निर्रक्त किया है। 'हीर एक्सप्रेस' के इस दूसरे आते हैं। साथ ही, चार्लेट डेविल और लेटेन बॉय जैसे विटिड कलाकारों की निपटूरी इस गाने को एक इंटरनेशनल अपील देती है।

गाने की कोरियोग्राफी की डिग्निटारी संभाली है अद्वितीय शैली ने - जिन्होंने अपने सिनेमैटिक स्टूडियो का दिल और यूरोपियन धार्मिक बुद्धसूली से निर्रक्त किया है। 'हीर एक्सप्रेस' के इस दूसरे आते हैं। साथ ही, चार्लेट डेविल और लेटेन बॉय जैसे विटिड कलाकारों की निपटूरी इस गाने को एक इंटरनेशनल अपील देती है।

COURT NOTICE (U/o 5 Rule 20 CPC) IN THE COURT OF Sh. Amit Sheoran Additional Civil Judge (Senior Division), Maham Sukhbir Singh S/o Late Ishwar Vs. General Public CNR No. HRRMA0-000169-2025 Next Date: 03-11-2025

(It is therefore prayed that a decree for declaration in favour of the plaintiffs and against the defendants may kindly be passed to the effect that the plaintiff is entitled to correct his name as Sukhbir Singh s/o Late Sh. Ishwar instead of wrong name Satbir s/o Late Sh. Ishwar and as a consequential relief of mandatory injunction may kindly be passed in favour of the plaintiff and against the defendants and direct the defendants no.2 to correct the entry in the revenue records as Sukhbir Singh s/o Late Sh. Ishwar instead of wrong name Satbir s/o Late Sh. Ishwar. Suit for declaration with consequential relief of mandatory injunction.)

PUBLICATION ISSUED TO: General Public

In above titled case, the defendant(s) respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 03-11-2025 at 10:00 a.m.

For details login to https://highcourtchd.gov.in/?mod=distrcnt_notice&distrcnt=Rohtak

Sd/- Jitesh Kumar Sharma, Civil Judge (Senior Division), Maham Dated, this day of 04-07-2025

ई-नीलामी सूचना

अंतिम प्रस्तावित लाभमा 13,000 कि.ग्रा. फॉसफोर/टोलर टैरिज, लगभग 4,500 कि.ग्रा. नीऑन और जल वातियोगत रेडस स्टॉक लगभग 35,000 कि.ग्रा.

इच्छुक खरीदारों को "प्रति क्रि. नं." आधार पर "अंतिम प्रस्तावित लाभमा 13,000 कि.ग्रा. फॉसफोर/टोलर टैरिज, लगभग 4,500 कि.ग्रा. नीऑन और जल वातियोगत रेडस स्टॉक लगभग 35,000 कि.ग्रा." के विवरण हेतु ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अनिवार्य किया जाता है। विषय सूचना "ई-नीलामी" आधार पर "को भी ई-वॉरंट है" और "प्रकारित नहीं" आधार पर बेचा जाएगा और भी, पानोस टैक्स/टैक्स से सम्बन्धित है। विषय सामग्री का निर्धारण खरार नं. 40/3, खेद नं. 574, खती नं. 810, गांव व.ड. सुताना निजट गांव पुस्तक लिज, ऊदराल, चंडी, पानोस, इत्यादि-132105 में केवल फॉसफोर को 09.07.2025 से 17.07.2025 के बीच पूर्ण, 10.00 बजे से अर्ध, 5.00 बजे के बीच किया जा सकता है। निरीक्षण हेतु कृपया श्री प्रवीण अग्रवाल से 9896044000 अथवा श्री रिकू से 8199037834 पर सम्पर्क करें।

PUBLICATION ISSUED TO: General Public

In above titled case, the defendant(s) respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 03-11-2025 at 10:00 a.m.

For details login to <https://www.seamthedeal.com/> में डायनोड करें

नीलामकतों : सील डि लीज जिसका पीलीकृत कार्यालय 148, पीछेट सी2, सेक्टर-5, रोहिणी दिल्ली-110085 है।

प्राप्त और ईमेल की डिमांड ड्रापर जमा करवाने की अन्तिम तिथि 17.07.2025 है।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्पले/बिलबोर्ड/टोलर टैरिज) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

भारत में हाइड्रोजन मांग 2032 तक 88 लाख टन होगी

नई दिल्ली। देश में हाइड्रोजन की मांग 2032 तक तीन प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 88 लाख टन प्रति वर्ष होने की उम्मीद है। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन (आईएसए) की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह के पहले दिन यहां जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 90 लाख टन सालाना से अधिक क्षमता की हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं की घोषणाओं के बावजूद, उनमें से कुछ ही अंतिम निवेश निर्णय पर पहुंच पाई हैं या धरलू अथवा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से दीर्घकालिक खरीद को लेकर समझौते किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 19 लाख टन सालाना हरित हाइड्रोजन परियोजना घोषणाओं में से 82 प्रतिशत चार राज्यों में हैं। ये राज्य हैं... ओडिशा (38 प्रतिशत), गुजरात (26 प्रतिशत), कर्नाटक (12 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (6 प्रतिशत)। घोषित परियोजनाओं में से लगभग 72 प्रतिशत अमेरिका उत्पादन के लिए हरित हाइड्रोजन के उपयोग को को लेकर है। जबकि 20 प्रतिशत ने अंतिम उपयोग के बारे में घोषणा नहीं की है।

रंस्कृति मंत्रालय भारत सरकार

निविदा सूचना

यूजर-फ्रेंडली डिजिटल रिपोजिटरी और वेब-कम-मोबाइल एप्लीकेशन सहित डिजिटल डेटा स्टोरेज के साथ-साथ कार्य के क्षेत्र में विनिर्दिष्ट अन्य टारगट हेतु व्यापक सोल्यूशन के लिए आरएफपी।

निविदा दस्तावेज संस्कृति मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट : indiaculture.gov.in और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल : eprocure.gov.in/eprocure/app से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

बोली जमा करवाने हेतु अन्तिम तिथि 28 जुलाई 2025 है।

सीबीसी-09101/11/0009/2526

हरियाणा सरकार निविदा सूचना

क्र. सं. प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	सूचने की तिथि	गोपनीयता (समाप्त) रू. में	बोड/निष्प. प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/सम्पर्क विवरण/ ई-मेल
1	एचवीपीएनएल रेवाड़ी क्षेत्र में टर्नकी आधार में 132 केवी ट्रांसमिशन लाईंस का निर्माण।	07.07.2025 01.08.2025	ईएफपी 120.18 लाख	www.hvnpn.org.in	0172-2583789 PRO@HVNP.ORG.IN

अधिक जानकारी हेतु कृपया धार्यः www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in संचाद-13/2026/40/36377/1/88/6 दि. 08.07.25

राशिफल

किरी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के सान्निध्य मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

मेघ

वर्ष के क्रोध से बचे। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। किसी मित्र से वस्त्र उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है।

वृष

आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। वाणी में महसूस रहेगी। कार्यक्षेत्र में कठिनायियां आ सकती हैं। परिश्रम भी अधिक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

मिथुन

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न रहेगा, परन्तु बातचीत में सन्तुलित रहें। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। तरक्की भी हो सकती है। आय बढ़ेगी।

कर्क

आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, परन्तु धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

सिंह

मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है। कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद-विवाद से बचे।

कन्या

आत्मविश्वास में कमी रहेगी। बातचीत में सन्तुलन बनाये रखें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाग-दौड़ अधिक रहेगी।

तुला

आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

वृश्चिक

आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। परन्तु अति उत्साही होने से बचे। संयत रहें। माता का साथ मिलेगा। आय भी बढ़ेगी। संतान को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं।

धनु

माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं। तरक्की के योग बन रहे हैं।

मकर

अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, परन्तु कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। भाइयों का सहयोग रहेगा।

कुंभ

शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा।

मीन

कुछ सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की शर्त हटाई अब नहीं पड़ेगी बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत?

एजेंसी ► नई दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब न्यूनतम बैलेंस की शर्त को हटाने पर विचार कर रहे हैं। कैनाल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक जैसे दिग्गज सरकारी बैंकों ने हाल ही में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता को हटा दिया था। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और बैंकों के बीच हुई एक बैठक में यह मुद्दा उठा। मंत्रालय ने सौधा सवाल किया कि जब अधिकांश बैंकिंग सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं, तो फिर ग्राहकों पर बैलेंस का बोझ क्यों डाला जा रहा है। मिनिमम बैलेंस से मतलब एक बैंक खाते में बनाए रखे जाने वाली वह रकम है, जिसके न रहने पर

खाता चलाता रहे। सरकारी बैंकों की बजाय निजी बैंकों के मिनिमम बैलेंस को लेकर नियम ज्यादा कड़े हैं।

आरबीआई की रिपोर्ट से खड़े हुए कान

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी फाइनैशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट में संकेत दिए हैं कि अब बैंकों को देनदारी प्रोफाइल बदल रही है। अब बैंक ज्यादा भरोसा सावधि जमा (टर्म डिपॉजिट) और वाणिज्यिक पत्र (सीडीएस) पर कर रहे हैं, जो ज्यादा ब्याज वाले साधन हैं। वहीं, कम लागत वाले चालू और बचत खातों में जमा राशि की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

शब्द पहेली - 5922

1	2	3	4	5	6
7		8		9	
	10		11	12	
13		14		15	16
		17		18	
19	20	21	22	23	24
		25			
26	27	28	29		
	30	31	32	33	
34	35	36			
			37		
38			39		

बाएँ से दाएँ

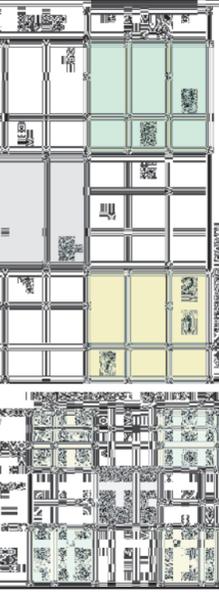
- राजीव गांधी की पत्नी का नाम-3,2
- उदारता, बडप्पन-4
- भोजन, खाद्य पदार्थ-2
- प्रहरी, रक्षा करने वाला-3
- अपशिष्ट पदार्थ-2
- कामदेव, चंद्रमा-4
- नाड़ी, नस-2
- जबरन, जबरदस्ती-3
- वायदा, वचन-2
- भवन, आलय-3
- आर्ट, हुनर-2
- ख्वाबगाह, आगमगाह, सोने का कमरा-5
- उद्देश्यहीनता-5
- परिणाम-2
- अंजन, नेत्रांजन-3
- सांझ, संध्य-2
- अधीन-3
- निश्चित-2
- निष्ठावन, सत्तानिष्ठ-4
- बेइमान, संभमार-2

36. दाम, मूल्य-3

- एक छोटी सवारी गाड़ी-2
- मुस्लिम कैलेंडर का एक महीना-4
- अश्रु, आंसू-5
- उपर से नीचे
- स्वर्ण, कनक-2
- गुजर करना-3
- धैर्यवान-3,2
- राशिचक्र की एक राशि-3
- आंशिक भोग हुआ-2
- सामंजस्य-4
- यायावर बंजारा-5
- चुनाव, वोटिंग-4
- दुख, कष्ट-2
- यज्ञ, होम-3
- कमरा, रूप-2
- उम्मीद, आस-2
- जुड़वा-3
- प्याला-2

22. हृदय, हार्ट-2

- निकृष्टतर-4
- बलवान, दमदार-5
- स्वदेशवासी-5
- आलसी, निरलल्ली-4
- बुरी आदत-2
- भरोसा, विश्वास-3
- आंचल, पल्लू-3
- अंग्रेजी शराब का एक प्रकार-2
- समय, वक्त-2



शब्द पहेली - 5921 का हल

श	म	म	सु	र	ल	न	की	र
नौ	ब	स	न	ग	म			
ज	प	ह	म	ला	व	र	म	ल
का	र	न	न	न	न	न	न	म
न	ख	ज	त	त	अ	न	मो	ल
र	ह	रा	म	खोर	ह			
अ	दि	की	त	ला	ज	मा	न	त
स	ग	म	म	सि	ह			
मा	र	क	म	त	र	ता	ह	ल
न	म	ला	ही	ज	इ	का		
म	स	ल	ह	क	ना	ग	त	

बिहार : उमेश नाम के शूटर से संपर्क किया, 4 लाख में हत्या की डील हुई

50 हजार एडवांस दिए, इन पैसों से शूटर उमेश ने अपने बच्चों की फीस भरी

बिल्डर अशोक साह ने कराया था कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर

पुलिस सीसीटीवी को ट्रेस करते हुए आरोपी के घर तक पहुंची। घर में जाने के उसके कपड़े, जूते अंदर से बरामद किए। इसके बाद उमेश को गिरफ्तार किया।

पूरे शहर के सीसीटीवी खंगाले, कपड़ों से हुई पहचान



हथियार भी हुए बरामद

आरोपी के कपड़ों से पहचान की गई। जहां तक वो सीसीटीवी में दिखा उसे ट्रेस किया गया। सीसीटीवी से हम बाइक को ट्रेस करते हुए आरोपी के घर तक पहुंचे। घर में जाने के बाद हमने वो कपड़े, जूते अंदर से बरामद किए। इसके बाद हमने उमेश यादव को गिरफ्तार किया। उसके घर से ही 59 राउंड गोलियां भी मिली थीं। घटना में इस्तेमाल हथियार भी उमेश के घर से मिला था।

जमीन को लेकर हुई गोपाल खेमका की हत्या

पूछताछ में उमेश ने अशोक साह का नाम लिया। उसने बताया कि सुपारी अशोक साह ने ही दी थी। दोनों मालदा के थे। शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी। 'डेढ़ महीने पहले हत्या की प्लानिंग हुई थी। अशोक साह के मोबाइल में जमीन विवाद की बातचीत की

कई रिकॉर्डिंग मिली है। पुलिस का कहना है कि खेमका की हत्या जमीन विवाद में ही हुई है। अशोक साह के घर से टैरो जमीन के कागजात मिले हैं। अशोक साह कोतवाली थाना इलाके के उदयगिरी अपार्टमेंट के प्लैट नंबर 601 में रेंट पर रहता था।

हत्या का मुख्य संदिग्ध पटना में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया

उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के मामले का एक प्रमुख संदिग्ध पटना के दमरिया घाट इलाके में सोमवार देर रात पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध विकास उर्फ राजा (29) कई अन्य अपराधिक मामलों में भी वांछित था। एक अधिकारी ने बताया कि हत्या मामले की जांच कर रहे अधिकारियों की टीम गुप्त सूचना के आधार पर विकास की तलाश में देर रात करीब दो बजकर 25 मिनट पर दमरिया घाट पहुंची। पुलिस अधिकारी ने बताया, "पुलिस कर्मियों को देखते ही उसने भागने की कोशिश की और गोलियां भी चलाई। अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें वह मारा गया।" उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई है। अधिकारी ने बताया कि मौके से एक पिस्तौल एवं कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा, "आशंका है कि विकास ने ही खेमका की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार मुहैया कराया था।" पुलिस ने पहले ही उमेश राय नामक बंदूकधारी को गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है।

विपक्ष के आरोपों पर इसी की दो टूक यह पूरी तरह 'समावेशी' प्रक्रिया सभी आरोप बेबुनियाद और बेतुके मतदाता सूची संशोधन पर बिहार में सियासी तूफान

एजेसी नई दिल्ली

बिहार की मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर तगड़ा हमला बोला है। इस बीच चुनाव अधिकारियों ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह समावेशी है। इसमें सब कुछ समाहित किया गया है। इसे लेकर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं। विपक्ष ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर हमला तेज कर दिया है। उनका कहना है कि इससे करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार को बिहार में मतदाता सूची संशोधन या गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।



कोर्ट भी पहुंचा मामला

विपक्षी दलों कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, जेएमएम, सीपीआई और सीपीआई (एमएल) के नेताओं ने मामले में मिलकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कई अन्य याचिकाएं भी इस साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनावों से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं।

नीतीश सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण स्थायी निवासियों तक किया सीमित

पटना (भाषा)। बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को निर्णय लिया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण अब केवल राज्य की स्थायी निवासियों तक ही सीमित रहेगा। यह निर्णय राज्य में चुनाव से महज कुछ महीने पहले लिया गया है, जब सरकारी नौकरियों में अधिवास नीति लागू करने की मांग बढ़ रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (मंत्रिमंडल सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा, "मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण को केवल बिहार की स्थायी निवासियों के लिए ही सीमित किया गया है।

युवा आयोग की घोषणा

नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार युवा आयोग गठित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे "राज्य में रोजगार के अवसरों की कमी" के आरोपों के बीच, विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले यह निर्णय लिया गया है।

पश्चिम बंगाल के मालदा में बवाल मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदुओं पर निशाना, दुकानों पर बांस से हमला



सरकार के इंतजाम रहे नाकाफी

अब से 24 घंटे पहले देशभर में मोहर्रम का जुलूस निकाला गया। पूरे देश में मोहर्रम के जुलूस के लिए खास इंतजाम किए गए थे। पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर था। प्रशासन ने अपनी तरफ से हुजुदंग और हिंसा रोकने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने मुहर्रम के जुलूस को शक्ति-प्रदर्शन में बदल दिया। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में जगह-जगह मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसा हुई। बिहार में पूर्वी चंपारण में अजय यादव की तलवार से काट कर हत्या कर दी गई। अजय स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। उनके बड़े भाई पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। यह घटना इंग्लिशबाजार इलाके की है, जहां रविवार शाम ताजिया निकाले जाने के दौरान विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि जब मुहर्रम का जुलूस लक्ष्मीकांतपुर गांव के पास से गुजर रहा था, तभी जुलूस में शामिल कुछ लोगों पर स्थानीय दुकानों पर बांस और लाठियों से हमला करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह विवाद अमरूद के पेड़ की डाल काटने को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस के अनुसार, दो दुकानों पर बांस से हमला किया गया, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया।

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में अगले सप्ताह होगी फांसी

नई दिल्ली (ब्यूरो)। केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में अगले सप्ताह 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जाएगी। यमन के एक नागरिक की हत्या के आरोप में वहां की अदालत ने यह फैसला सुनाया था। जिस पर पिछले साल 2024 में यमन के राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। वहीं, इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय कड़ी निगरानी रखे हुए है। जिसमें वह न केवल यमन में अधिकारियों के साथ संपर्क में बना हुआ है। बल्कि निमिषा के परिवार के भी लगातार संपर्क में है। जिसका उद्देश्य उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना है। निमिषा ने वर्ष 2008 में नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गृह राज्य केरल में ही नौकरी की शुरुआत की।

माजपा की चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट

नई दिल्ली (ब्यूरो)। माजपा की चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने गत 25 जून को दक्षिण कोलकाता में लॉ कॉलेज में 24 साल की छात्रा के साथ कथित गैररूप की घटना की जांच रिपोर्ट मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी। इस टीम का नेतृत्व पूर्व कैदीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने किया, जिसमें मौनक्षी लेखी, बिप्लब कुमार देब और मनन कुमार मिश्रा शामिल थे। मंगलवार को नड्डा को रिपोर्ट सौंपने के बाद माजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए टीम ने आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासन ने उनके साथ सहयोग नहीं किया। साथ ही टीम ने मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है। पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह ने आरोप लगाया कि एक महिला मुख्यमंत्री होकर भी ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है।

जेन स्ट्रीट की जांच 2024 में शुरू हुई नियामकीय विफलता का सवाल नहीं : बुच

नई दिल्ली (ब्यूरो)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने मंगलवार को कहा कि पूंजी बाजार नियामक अप्रैल, 2024 से जेन स्ट्रीट मामले पर नजर रखे हुए है। उन्होंने नियामकीय विफलता का आरोप लगाने के प्रयासों को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया। मीडिया में आ रही खबरों के बाद लिखित बयान में बुच ने जेन स्ट्रीट के खिलाफ सेबी के अंतरिम आदेश के घटनाक्रम का उल्लेख किया। सेबी ने विदेशी हेज कोष जेन स्ट्रीट पर हेराफेरी के जरिये वायदा एवं विकल्प सौदों से अर्जित 4,800 करोड़ रुपये से अधिक राशि को जब्त करने और उसकी बाजार पहुंच रोकने का पिछले सप्ताह आदेश जारी किया था। बुच ने बयान में कहा, "यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया का एक वर्ग स्पष्ट तथ्यों

सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और केंद्र की मोदी सरकार पर भारतीय शेयर बाजार में अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट द्वारा कथित हेरफेर और अवैध मुनाफाखोरी को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने सेबी की निष्कियता और छोटे निवेशकों को गंभीर नुकसान होने देने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

को नजरअंदाज कर रहा है और यह कहकर गलत कहानी गढ़ने का प्रयास कर रहा है कि सेबी की ओर से नियामकीय विफलता हुई है।" बुच ने कहा कि घटनाक्रम से पता चलता है कि सेबी ने मामले की जांच अप्रैल, 2024 में ही शुरू कर दी थी।

हरियाणा सरकार

"सरकार ने समस्याओं के स्थायी समाधान देने का प्रयास किया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र भी पराली का उपयोग करेंगे। इससे किसानों को कृषि-कचरे से अतिरिक्त आय भी होगी।"

- नरेन्द्र मोदी

पराली सप्लाई चेन (फसल अवशेष प्रबंधन) पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित, वर्ष 2025-26

प्रोजेक्ट लागत मूल्य 1 करोड़ रुपये अथवा 1.5 करोड़ रुपये।

प्रथम विकल्प : परियोजना लागत का 65% अनुदान, 25% उद्योग एवं 10% एग्रीगेटर का अंशदान।

द्वितीय विकल्प : 65% अनुदान एवं 35% एग्रीगेटर का अंशदान।

लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति तथा राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा।

आवेदन हेतु कृषि पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाएं।

कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2025

अधिक जानकारी के लिए

टोल फ्री नं० **1800-180-2117** या ज़िला कृषि उप-निदेशक से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

www.agriharyana.gov.in

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा

www.prharyana.gov.in | Follow us on

चिंतन

अमेरिका से टैरिफ वार्ता में अधिक सावधान रहे भारत

अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने में भारत को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। अमेरिका अपने जीएम समेत अन्य कृषि व पोल्ट्री उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को गिद्ध नजर से देख रहा है। यह नजर बहुत लंबे समय से है। भारत ने जब अंतरराष्ट्रीय दबाव में गेट (अब डब्ल्यूटीओ) समझौते को वर्ष 1994 में स्वीकृति दी थी, उसके बाद से ही भारत पर अपने कृषि व संबद्ध क्षेत्र को खोलने का अमेरिकी दबाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत पर शुल्क (टैरिफ) को लेकर अधिक दबाव है। अमेरिका को लगता है कि भारत अपने सामानों पर अमेरिका से अधिक टैरिफ वसूलता है, जबकि अमेरिकी सामानों पर कम शुल्क देता है। बेशक वस्तुओं के व्यापार भारत के पक्ष में है, लेकिन अमेरिका भूल जाता है कि सेवाओं के ट्रेड में अमेरिका का पलड़ा भारी है। भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ता में सर्विस टैरिफ तरीके से ही व्यापार चलते रहेंगे। अमेरिका ने नौ जुलाई तक जवाबी शुल्क को निलंबित कर दिया था। इस कारण भारत पर दबाव था कि वह नौ जुलाई से पहले ही ट्रेड वार्ता पूरी कर ले, लेकिन अब अमेरिका ने अपनी समय सीमा को एक अगस्त तक बढ़ा दिया है। यानी कि अब एक अगस्त तक पुराने टैरिफ तरीके से ही व्यापार चलते रहेंगे। इससे भारत के निर्यातकों को राहत मिली है, इसी के साथ भारत को ट्रेड वार्ता के लिए अब तीन हफ्ते का वक्त और मिल गया है। ऐसे में भारतीय वार्ताकारों को असहमति वाले मुद्दों को सुलझाने में निगोशिएट करने को अधिक सोच-विचार का समय होगा। हालांकि, यदि भारत इस महीने के अंत तक अमेरिका के साथ कम से कम वस्तुओं पर बीटीए (द्विपक्षीय व्यापार समझौता) को अंतिम रूप दे देता है तो तुलनात्मक रूप से अधिक फायदे में होगा। वित्त वर्ष 2021-22 से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। वस्तुओं का आपसी व्यापार 2024-25 में 131.84 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था। इसमें 86.51 अरब डॉलर का निर्यात व 45.33 अरब डॉलर का आयात था। भारतीय कृषि संगठनों ने सरकार से अमेरिकी कृषि व पोल्ट्री उत्पादों के लिए भारतीय बाजार न खोलने की अपील की है, हालांकि नीति आयोग के कई सदस्य जीएम फसलों की पैरवी कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर दावा किया है कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौता करने के करीब हैं, लेकिन भारत को किसी भी अमेरिकी झांसे व दबाव में नहीं आना चाहिए, ट्रेड और टैरिफ में अपना हित देखना जरूरी है। भारत को अपने कृषि व संबद्ध क्षेत्र और एमएसएमई की रक्षा करनी चाहिए। सरकार को आर्थिक शोध संस्थान थिंक टैंक जीटीआरआई के अमेरिका के साथ व्यापार समझौते संबंधी सुझावों को गंभीरता से लेना चाहिए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप का 'रिसेप्रोकल टैरिफ मॉडल' मुक्त व्यापार समझौते का नहीं, बल्कि अमेरिकी घाँस है। इसलिए भारत को अमेरिकी समय सीमा के जाल में नहीं फँसना चाहिए। जिन टैरिफ मुद्दों पर आपसी सहमति बनती जा रही है, उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करते जाना चाहिए। असहमति वाले मुद्दों पर वार्ता जारी रखनी चाहिए। एकतरफा अमेरिकी शुल्क वृद्धि विश्व व्यापार संगठन के नियमों का भी उल्लंघन है और इससे वैश्विक व्यापार प्रवाह बाधित होने, अमेरिका में उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि होने और वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में जटिलताएं उत्पन्न होने की आशंका है। शुल्क वृद्धि अमेरिका पर भारी पड़ेगी, भारत को तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है।

नाली व्यवस्था

पंकज चतुर्वेदी



ऐसे शहर तो डूबेंगे ही

पिछले एक दशक में 25 हजार करोड़ बस इस बात को खर्च किए गए कि देश के प्रगति के प्रतिमान कहलाने वाले शहर बरसात में दरिया न बन जाएं, लेकिन हालत बदले नहीं। मौसम की बरसात के शुरूआत में ही दरिया बन गए और जो समाज कुछ दिनों पहले तक नालों में पानी की एक-एक बूंद के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा था, अपने गली-मुहल्लों में गर्दन तक पानी में डूब गया। जो चौड़ी सड़कें या फ्लाईओवर यातायात को फर्स्ट से निकालने के लिए बने हैं, वहां मीलों तक वाहनों का जाम हो जाता है। यह रोग अब महानगरों में ही नहीं, जिला स्तर के नगरों में भी आया है। चूँकि बरसात के दिन कम हो रहे हैं, सो लोग इसे अस्थाई दिक्कत मानकर बिसरा देते लेकिन जान लें कि अब हमारा देश भी शहरीकरण की ओर अग्रसर है। उसके चलते जल्द ही जलभराव गंभीर समस्या का रूप ले लेगा। पिछले साल बजट सत्र के आखिरी दिनों में यह बात संसद में स्वीकार की गई थी कि केंद्र सरकार बारिश के पानी की निकासी के लिए शहरों पर बीते 10 वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। इसके बावजूद हर बारिश के दौरान शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और पानी उतरने में घंटों लगते हैं। दुखद तो यह है कि देश के 100 शहर जिन्हें स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया, पहले से अधिक डूब रहे हैं। सरकार कहती है कि जुलाई 2024 तक, 100 शहरों ने स्मार्ट सिटी मिशन के हिस्से के रूप में 1,44,237 करोड़ की राशि की 7,188 परियोजनाएं (कुल प्रोजेक्ट का 90 प्रतिशत) पूरी कर ली है। 19,926 करोड़ की राशि की शेष 830 परियोजनाएं भी पूरा होने के अंतिम चरण में हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के 35 शहरों में बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए 1,005 करोड़ रुपये के 87 प्रोजेक्ट बनाए गए। इतना ही नहीं, 100 स्मार्ट सिटी में से 97 शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में सुधार के लिए 603 प्रोजेक्ट बनाकर 21,182 करोड़ रुपये खर्च हुए। कहने की जरूरत नहीं कि ये सभी शहर बरसात में जलभराव के कारण ठप हुए। शहरीकरण आधुनिकता की हकीकत है और पलायन इसका मूल, लेकिन नियोजित शहरीकरण ही विकास का पैमाना है। गांवों का कस्बा बनना, कस्बों का शहर और शहर का महानगर बनने की प्रक्रिया तेज हुई है। विडंबना है कि हर स्तर पर शहरीकरण की एक ही गति-भंगति रही, पहले आबादी बढ़ी, फिर खेत में अनाधिकृत कॉलोनी काटकर या किसी सार्वजनिक पार्क या पहाड़ पर कब्जा कर अधकच्चे, उजड़े से मकान खड़े हुए। कई दशकों तक ना तो नालियां बनीं या सड़क और धीरे-धीरे इलाका 'अरबन-स्लम' में बदल गया। गौर करने लायक बात यह भी है कि साल में ज्यादा 25 दिन बरसात के कारण बेहाल हो जाने वाले ये शहरी क्षेत्र पूरे साल में आठ से दस महीने पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना का एक शोध बताता कि नदियों के किनारे बसे लगभग सभी शहर अब थोड़ी सी बरसात में ही दम तोड़ देते हैं। दिक्कत अकेले बाढ़ की ही नहीं है, इन शहरों की दुरूपट मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता अच्छी नहीं होती है। शहरों में अब गलियां में भी सीमेंट पोत कर आरसीसी सड़कें बनाने का चलन बढ़ गया है और औसतन बीस फीसदी जगह ही कच्ची बची है, सो पानी सोखने की प्रक्रिया नदी-तट के करीब की जमीन में तेजी से होती है। शहरों में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण तो यहां के प्राकृतिक नदी-नालों, तालाब-जोहड़ों और उन तक नी लाने वाले मार्ग पर अवैध कब्जे, भूमिगत सीवरों की ठीक से सफाई ना होना है। इससे बड़ा कारण है हर शहर में हर दिन बढ़ते कूड़े का भंडार व उसके निबटाने की माकूल व्यवस्था ना होना। जाहिर है कि बरसात होने पर यही कूड़ा पानी को नाली तक जाने या फिर सीवर के मुँह को बंद करता है। महानगरों में भूमिगत सीवर जलभराव का सबसे बड़ा कारण है।

जब हम भूमिगत सीवर के लायक संस्कार नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर खुले नालों से अपना काम क्यों नहीं चला पा रहे हैं? एक बात और बंगलुरु या हैदराबाद या दिल्ली में जिन इलाकों में पानी भरता है वहां की कुछ दशक पुरानी जमीनी संरचना का रिकार्ड उठा कर देखें तो पाएंगे कि वहां पर कभी कोई तालाब, जोहड़ या प्राकृतिक नाला था। महानगरों में बाढ़ का मतलब है परिवहन और लोगों का आवागमन ठप होना। जलभराव और बाढ़ मानवजन्य समस्याएं हैं और इसका निदान दूरगामी योजनाओं से संभव है; यह बात शहरी नियोजनकर्ताओं को भनी-भाँति जान लेना चाहिए और इसी सिद्धांत पर भविष्य की योजनाएं बनाना चाहिए। शहर को डूबने से बचना है तो कूड़ा कम करने, पॉलीथिन पर पाबंदी, सीवरों की ईमानदारी से नियमित सफाई जरूरी है। शहरों में अधिक से अधिक खाली जगह यानि कच्ची जमीन हो, ढेर सारे पेड़ हों। जलभराव वाली जगह भूजल रिचार्ज के प्रयास हों। प्राकृतिक जलाशयों, नदियों को उनके मूल स्वरूप में रखने तथा उसके जलग्रहण क्षेत्र को किसी भी किस्म में निर्माण ना हों।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)



आर्थिकी

प्रो. अश्वनी महाजन

अमेरिका अपने व्यापार भागीदारों पर अमेरिकी उत्पादों पर उनके द्वारा लगाए गए शुल्क को कम करने और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने के लिए दबाव डालता हुआ दिखाई दिया, ताकि अमेरिका द्वारा पारस्परिक शुल्क लगाए जाने से बचा जा सके। उधर, भारतीय नीति आयोग द्वारा तैयार कार्य पत्र ने किसान संगठनों में भारी रोष पैदा कर दिया है। उनका कहना है कि अगर ये सुझाव मान लिए गए तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। इसी तरह, समझौते में लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। डेटा संग्रभुता और आईपीआर भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका हमें जितना दे सकता है, उससे कहीं अधिक मांग कर रहा है।

अमेरिका से ट्रेड समझौते में रुकावटें

भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर 2017 से ही चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इस समझौते को मूर्त रूप नहीं मिल पाया है। कई बार तो यह समझौता इतना नजदीक नजर आता था कि मीडिया ने एफटीए के मुख्य तत्वों की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन अचानक कुछ बाधाएं सामने आतीं और एफटीए ठंडे बस्ते में चला जाता। आखिरी बार ऐसी घटना 2020 में हुई थी। मीडिया में खबरें आ रही थीं कि भारत-अमेरिका एफटीए पर हस्ताक्षर होने वाले हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) का भारत दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अचानक पता चला कि यूएसटीआर ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है और तब से भारत-अमेरिका एफटीए पर कोई चर्चा नहीं हुई।

हाल ही में इस एफटीए, तो कभी सीमित एफटीए के बारे में खबरें फिर से आना शुरू हुईं। पिछले चार महीनों में जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से ये चर्चाएं एक बार फिर सामने आने लगी हैं। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यापार भागीदारों पर पारस्परिक शुल्क लगाने का फैसला किया, जिससे अब शुल्क अमेरिका के लिए डब्ल्यूटीओ द्वारा सहमत बाध्य दरों के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की सनक के आधार पर, पारस्परिकता के तथाकथित विचार पर तय किए जा रहे थे। अमेरिका अपने व्यापार भागीदारों पर अमेरिकी उत्पादों पर उनके द्वारा लगाए गए शुल्क को कम करने और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने के लिए दबाव डालता हुआ दिखाई दिया, ताकि अमेरिका द्वारा पारस्परिक शुल्क लगाए जाने से बचा जा सके। ऐसी परिस्थितियों में, व्यापार विशेषज्ञ, जो मुक्त व्यापार के समर्थक माने जाते हैं, ने कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने का यह सही समय है, अब एफटीए के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है ताकि हम पारस्परिक शुल्क से बच सकें, और अमेरिका के साथ पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते के आधार पर भारत-अमेरिका व्यापार को बढ़ावा दे सकें।

बातचीत चल रही थी और मीडिया में यह बताया जा रहा था कि भारत-अमेरिका एफटीए किसी भी समय हो सकता है और किसी भी दिन इस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि शुक्रवार, 13 जून को ऐसी खबरें आना शुरू हो गईं कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में एक बार फिर से बाधा आ गई है और शायद भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द ही नहीं होगा। इस बार तथाकथित अवरोध भारत के इस स्पष्ट रुख से आया है कि वह जीएम खाद्य उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं

दे सकता, जबकि अमेरिका जीएम खाद्य उत्पादों के लिए भारत के बाजार को खोलने पर जोर दे रहा है। अमेरिकी व्यवसायों द्वारा भारत में डेटा होस्ट करने के लिए सर्वर की अनुमति नहीं देने के खिलाफ डेटा स्थानीयकरण पर हमारा जोर, और कुछ अन्य मुद्दों के कारण प्रस्तावित एफटीए फिर से खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। 2006-08 के आसपास, रणनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की व्यापक बातचीत के बीच भारत-अमेरिका एफटीए का विचार सामने आया था। हालांकि, प्रमुख मतभेदों के कारण कोई औपचारिक वार्ता शुरू नहीं हुई। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका भारतीय



बाजारों में, विशेष रूप से खुदरा, कृषि आदि में, अधिक पहुंच और आईपीआर पर डब्ल्यूटीओ के तहत अनुमत से अधिक रियायतें चाहता था, जिसे हम डब्ल्यूटीओ प्लस कहते हैं। भारत के इस रुख के कारण, कि इस समझौते से नीतिगत गुंजाइश खत्म हो सकती है, खासकर कृषि, दवा, आईपीआर और निवेश नियमों के मामले में। जबकि कई विशेषज्ञ भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खाके के बारे में चिंता कर रहे हैं, हमें अमेरिका की मांगों को समझने की जरूरत है, और किसी एक या अधिक मुद्दों पर झुکنे से भारत को कैसे नुकसान हो सकता है, इस पर बहस करने की जरूरत है।

हमें यह जानने की जरूरत है कि चूँकि कई अमेरिकी टैरिफ भारत द्वारा निर्यात नहीं किए जाने वाले उत्पादों को लक्षित करते हैं, इसलिए पारस्परिक शुल्क भारतीय निर्यातकों को महत्वपूर्ण रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हम व्यापार सौदों के माध्यम से श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकते हैं, जो कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और सौर उपकरण जैसे विनिर्माण उद्योगों को भारत के मेक

इन इंडिया अभियान के साथ तालमेल बिठाते हुए, अमेरिकी बाजारों तक पहुंचने और पैमाने हासिल करने में मदद कर सकता है। अगर यह सीमित व्यापार सौदों के माध्यम से भी हासिल किया जा सकता है, तो यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि एक पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते से सरकारी खरीद, कृषि सब्सिडी, आईपी अधिकार और उदारीकृत डेटा प्रवाह पर दबाव आवेगा। ये वे क्षेत्र हैं, जिनका भारत लंबे समय से विरोध करता रहा है। पूर्ण व्यापार सौदे का एक और नकारात्मक पहलू यह है कि अमेरिका भारत पर ऊर्जा और रक्षा वस्तुओं के आयात को बढ़ाने का दबाव डाल सकता है, जब तक कि इसका प्रतिकार नहीं किया जाता है, तब तक भारत की व्यापार स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए, यह उचित होगा, अगर भारत शून्य से शून्य टैरिफ की पेशकश करे, जैसे कि यह संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर कम जोखिम वाली श्रेणियों में टैरिफ में कटौती का आदान-प्रदान हो। साथ ही हमें सेवाओं, सरकारी खरीद, आईपी और कृषि पर बाध्यकारी समझौतों से बचने की जरूरत है। प्रस्तावित भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते में दो प्रमुख विवादस्पद मुद्दे कृषि और एमएसएमई के हैं। हम जानते हैं कि कृषि भारत के 45 प्रतिशत से अधिक कार्यबल को रोजगार देती है, और कोई भी समझौता जो कृषि को प्रभावित करता है, वह राष्ट्र की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को खतरों में डाल सकता है। इस बीच, आश्चर्यजनक रूप से नीति आयोग ने एक कार्य पत्र जारी किया है, जिसमें अमेरिका से आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सोयाबीन और मक्का जैसे कृषि उत्पादों के आयात पर शुल्क कम करने और साथ ही पोल्ट्री और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करने का सुझाव दिया गया है।

नीति आयोग द्वारा तैयार कार्य पत्र ने किसान संगठनों में भारी रोष पैदा कर दिया है। उनका कहना है कि अगर ये सुझाव मान लिए गए तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। इसी तरह, समझौते में लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। डेटा संग्रभुता और आईपीआर भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका हमें जितना दे सकता है, उससे कहीं अधिक मांग कर रहा है। हमें यह समझने की जरूरत है कि अमेरिका के साथ समझौता हो या न हो, भारत से अमेरिका को निर्यात बिना रोक-टोक जारी रहेगा और कोई कारण नहीं है कि हम एक सीमा से अधिक रियायतें दें, जिससे भारतीय कृषि, लघु उद्योग और अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास को नुकसान पहुंचे।

(लेखक पूर्ण प्रोफेसर, पंजीकृत लेखक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपडेट प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

पसंद और नापसंद से मुक्त होना जरूरी



संकलित

दर्शन

आपने देखा होगा कि लोग बड़े गर्व से अक्सर कहते हैं, 'मुझे यह पसंद है, इसलिए मैं यह करके रहूंगा और वह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए उसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्वाधीन हूँ।' क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यह सोच सचमुच आपको स्वाधीनता से जन्मा है? यह स्वाधीनता नहीं है, यह तो बेवसी है, लाचारी है। पसंद और नापसंद की बेड़ियों में आज लगभग पूरी मानवता जकड़ी हुई है। सभी पारिवारिक झगड़ों की जड़ में लोगों की व्यक्तिगत पसंद और नापसंद ही होती हैं। पसंद और नापसंद को लेकर समाज, राष्ट्र और धर्म तक बंटे हुए हैं। जब हमारे सोच का दायरा बहुत सीमित होता है, हम कई तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर हम पर पसंद और नापसंद की सनक सवार हो जाती हैं। तब हम उसे नहीं देख पाते, जिसकी जरूरत है। हम बर्ही करते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं। वह नहीं करते, जिसे किए जाने की आवश्यकता है। फिर शुरू होता है अविराम झंझटें व विवादों का सिलसिला और उसी में उलझकर रह जाता है हमारा लघु-जीवन। योग परंपरा में भीतरी आगम को बहुत गहराई से देखा गया और भीतरी पराधीनता से मुक्त होने की कई तकनीकों का आविष्कार किया गया, क्योंकि जो भीतरी पराधीनता का शिकार नहीं है, उसे कोई बाहरी शक्ति उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। पसंद और नापसंद की सनक से मुक्त होने के लिए हमें अपनी चेतना पर काम करना होगा। एक जागरूक व्यक्ति ही यह देख पाने में सक्षम होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या आवश्यक है और क्या किया जाना चाहिए।

अंतर्मन



25 साल बाद स्मृति ईरानी फिर सात भी कभी बर्ही-2 सीरियल में अभिनय करेंगी

ये आपके डायलॉग हैं मैडम इन्हें राजनीतिक भाषण जैसे ना बोलना

आज की पाती

सरकार फर्जी लोन एप्स से कड़ाई से निपटे

हमारे देश में विभिन्न कंपनियों ने एप्स के जरिए लोन देने की व्यवस्था की है, ताकि लोगों को आसानी से घर बैठे ही कुछ मिनटों में लोन उपलब्ध हो सके। लेकिन कुछ फर्जी एप्स भी हो सकते हैं। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, ताकि किसी फर्जी एप्स के जरिए लिया गया लोन मुसीबत न बने। जब किसी को आर्थिक सहायता आता है, या जब किसी का कोई परिवारजन बीमार होता है या जब किसी गरीब या मिडल क्लास के बच्चे की पढ़ाई का खर्चा पूरा न हो रहा हो या किसी व्यापारी को व्यापार के लिए धन की जरूरत हो तो ऐसे में इन सभी को सरकारी बैंकों या अन्य उचित एप्स से लोन आसानी से न मिल रहा है, तो ऐसे वर्ग के लोग फर्जी लोन एप्स के जंगल में फंस जाते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए सरकार को इन फर्जी एप्स से कड़ाई से निपटना चाहिए।

- रविंद्र जोशी, विलासपुर

मनोविज्ञान

डॉ. कविता सिंधू खरीटा



जल्द अनियंत्रित होती हैं नकारात्मक भावनाएं

हमारी भावनाएं हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करती हैं। कभी-कभी ये भावनाएं हमारे लिए प्रेरणा बनती हैं, तो कभी इतनी तीव्र हो जाती हैं कि हमें असह्य, असंतुलित और प्रमित कर देती हैं। विशेषकर नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, दुख, ईर्ष्या या असुरक्षा बहुत जल्दी नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं और हमारी सोच, निर्णय लेने की क्षमता, यहां तक कि हमारे संबंधों को भी प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन क्या नकारात्मक भावनाएं केवल परेशानी हैं? या इनमें कोई छिपा हुआ संदेश भी होता है? दरअसल, हमारी भावनाएं केवल रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, ये हमारे अंदरूनी संवाद का हिस्सा हैं। जब हम किसी स्थिति से आहत होते हैं, तो हमारी भावनाएं हमें सावधान करती हैं। यह बात तुम्हें परेशान कर रही है, इसे नजरअंदाज मत करो। यह एक प्रकार का प्राकृतिक चेतावनी संदेश है जो हमें सतर्क करती है और आत्म-सुरक्षा की भावना को जाग्रत करता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम इन भावनाओं को समझने की बजाय या तो दबा देते हैं या उनके साथ बहने लगते हैं। न तो इन्हें अनदेखा करना समाधान है, न ही इनके



को पहचानना और उन्हें सही नाम देना बेहद जरूरी है जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, से आगे जाकर कहें कि मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे अनदेखा किया गया। यह स्पष्टता आपको प्रतिक्रिया देने की बजाय सार्थक प्रतिक्रिया करने में मदद करेगी। अपने आप से बात करना बिना दोषारोपण के सबसे शक्तिशाली

अभ्यास है। भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें कोई रचनात्मक रूप दें। लेखन, चित्रकारी, संगीत, प्रार्थना ये सब माध्यम हैं अपने भीतर के द्रढ़ को शब्द और रूप देने के। गहरी सांस लेना, कुछ मिनट ध्यान करना, या केवल एकता में बैठना, यह आपके अंतर्मन को शांत करने में अत्यंत सहायक होता है। यह आपको वर्तमान क्षण में लाता है जहां न पछतावा है, न चिंता केवल शुद्ध उपस्थिति है। यदि हम इन भावनाओं को अपनी यात्रा का हिस्सा मान लें एक सहयात्री, जो हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जा रहा है तो हम भीतर से और भी मजबूत बन सकते हैं। हर बार जब आप अपने मन से सच्ची, करुणा भरी बातचीत करते हैं, तो आप एक नई समझ, संतुलन और दृष्टिकोण के साथ उभरते हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं ये आपके जीवन के अनुभवों से बुनी हुई हैं। इनका सम्मान करें। नकारात्मक भावनाएं यदि सही दिशा में समझी जाएं, तो वे भी आपके शांति, शक्ति और संतुलन की ओर ले जा सकती हैं। अपने भीतर की आवाज को नरम, सशक्त और करुणा भरी बनाएं। यही संवाद आपके जीवन की दिशा भी तय करता है।

(लेखिका शिक्षाविद् हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)



बिहार युवा आयोग गठित

बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा संरक्षण और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज केबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है।

-नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

आपदा प्रभावितों का दर्द

आपदा प्रभावितों का दर्द सुनकर मन बहुत ही व्यथित है। सराज अमी भी दर्द में डूबा है। त्रासदी ने हमारी टाटकों की मेहनत को कुछ सेकंड में ही तहस-नहस कर दिया। हमारे कई लोगों को हमसे छीन लिया। ईश्वर उन्हें सद्गति दे।

-नयराज ठाकुर, पूर्व सीएम, हिंगाचल

भारत की शानदार जीत

एजबेस्टन में भारत की शानदार जीत। निरुत्तर से खेले और इंग्लैंड को लगातार परेशान किया। खूबी ने आयातवादी प्रदर्शन किया। सिराज और आकश ने इस धिच पर जिस तरह की गेंदबाजी की, उसके लिए उनका विशेष उल्लेख है।

-विगत कोहली, क्रिकेटर

चिंता रॉकिंग चेयर जैसी

चिंता रॉकिंग चेयर के जैसी होती है, जो हमें हिलाती है पर ले कहीं नहीं जाती। समस्या के बारे में सोचना 'चिंता' है और समाधान के बारे में विचारना 'चिंतन'। चिंता स्वीकारे बिना हम चिंतन तक नहीं पहुंच सकते।

- अशुतोष राणा, अभिनेता

हमारा पता

हरिभूमि कार्यालय

नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहताक-124001 फोन: 9253681019-20 ई-मेल: haribhoomi@gmail.com वेब-साइट: www.haribhoomi.com

यह ऐसा आर्टिलरी गन सिस्टम है, जिसे कहीं भी लाने ले जाने में आसानी रहेगी। सेना अपनी जरूरत के हिसाब से थार रेगिस्तान से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक, किसी भी मोर्चे पर तैनात कर सकती है।

डीआरडीओ ने बढ़ाई भारतीय सेना की ताकत

एजेसी ►► पुणे

भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए पूरी तरह से देश में ही विकसित की गई आधुनिक तोप एडवॉन्स टोप आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस) अब तैयार है। इस तोप को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने पुणे में मौजूद आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एआरडीई) के साथ मिलकर और निजी कंपनियों जैसे भारत फोर्ज और टाटा एडवॉन्स सिस्टम्स के सहयोग से बनाया है। इसे जल्द से जल्द सेना के हवाले करने की तैयारी है। यह ऐसा आर्टिलरी गन सिस्टम होगा, जिसे कहीं भी लाने ले जाने में आसानी रहेगी। सेना अपनी जरूरत के हिसाब से थार रेगिस्तान से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक, किसी भी मोर्चे पर तैनात कर सकती है।

देशी तोप एटीएजीएस पूरी तरह से तैयार, 48 किमी दूर तक मार करने की क्षमता

टीएजीएस तोप दुनिया की सबसे बेहतरीन तोप प्रणालियों में से एक डीआरडीओ और निजी कंपनियों के संयुक्त प्रयास से बनाई गई है



307 तोपों का दिया गया ऑर्डर

ए. राजू ने बताया कि भारतीय सेना ने मार्च 2025 में 307 एटीएजीएस तोपों का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर को भारत फोर्ज और टाटा एडवॉन्स सिस्टम्स के बीच 60:40 के अनुपात में बांटा गया है। यानी 60% तोपें भारत फोर्ज बनाएंगी और 40% टाटा कंपनी। ये सभी तोपें पांच साल की अवधि में सेना को सौंपी जाएंगी।

25 बमों की क्षमता वाला बैरल

एआरडीई के निदेशक ए. राजू ने बताया कि यह प्रोजेक्ट 2012 में शुरू हुआ था और एआरडीई को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी। एटीएजीएस तोप दुनिया की सबसे बेहतरीन तोप प्रणालियों में से एक है। यह 155 मिमी / 52 केलिबर की तोप है। इसकी फायरिंग कैपेसिटी जोन सात में है, जिससे यह 48 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसमें 25 बमों की क्षमता वाला बैरल है। फिलहाल इसके लिए इस्तेमाल होने वाला गोला बास्केट अनाइडेड है, लेकिन हम गाइडेड यानी सटीक निशाना लगाने वाले गोले विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। इसे हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सके, और यह लगातार काम करने में सक्षम होनी चाहिए।

75% तक देश में ही बनी

एटीएजीएस प्रोजेक्ट डायरेक्टर आर.पी. पांडेय ने कहा कि यह तोप डीआरडीओ और निजी कंपनियों के संयुक्त प्रयास से बनाई गई है। इसकी फायरिंग कैपेसिटी जोन सात में है, जिससे यह 48 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। यह पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर आधारित है और 75% तक देश में ही बनी हुई है।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक में मोदी की दो टूक आतंकवाद पर मापदंड दोहरे न हों, इस लड़ाई में भारत-ब्राजील की सोच एक

दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में की व्यापक चर्चा

आतंकवाद पर मापदंड दोहरे न हों, इस लड़ाई में भारत-ब्राजील की सोच एक

पीएम ने अप्रैल में पहलगांम आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्रपति लूला की एकजुटता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया

एजेसी ►► ब्रासीलिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ब्राजील की शून्य सहिष्णुता और शून्य दोहरा मापदंड की सोच समान है। भारत और ब्राजील दोनों आतंकवाद और इसका समर्थन करने वालों का कड़ा विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और उसके सलाहकार मित्र चीन का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, 'आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारी सोच एक जैसी है- शून्य सहिष्णुता और शून्य दोहरा मापदंड।' पीएम मोदी ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि भारत और ब्राजील आतंकवाद और इसका समर्थन करने वालों का कड़ा विरोध करते हैं। अतीत में भारत ने पाकिस्तान को 'आतंकवाद का वैश्विक केंद्र' बताया है। पीएम मोदी ने चीन का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा, 'आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों के लिए कोई स्थान नहीं है।' पीएम ने अप्रैल में पहलगांम आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्रपति लूला की एकजुटता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

- प्रवासी भारतीयों ने तिरंगा थामे हाथ जोड़ पीएम मोदी का किया स्वागत
- ब्राजील के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे



राष्ट्रपति लूला ने मोदी का स्वागत

सांभा-रेवे, शिवतांडव स्तोत्र और शास्त्रीय नृत्य की बड़ी संलग्नधारा

पीएम नरेंद्र मोदी शिवस सम्मेलन में शामिल होने के बाद मंगलवार को द्विपक्षीय राजकीय यात्रा के लिए ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया पहुंचे, जो लगभग छह दशकों में किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा है। यहां पीएम मोदी का स्वामन्य पारंपरिक सांभा रेवे की संगीतमय प्रस्तुति से किया गया। इसके बाद होटल पहुंचने पर शिव तांडव स्तोत्र पाठ और भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भावपूर्ण प्रदर्शन किया गया। पीएम मोदी ने इसे 'यादगार स्वागत' बताया और प्रवासियों की अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए प्रशंसा की। पीएम मोदी ने लिखा कि ब्रासीलिया में भारतीय समुदाय ने यादगार स्वागत किया, जो एक बार फिर दर्शाता है कि हमारे प्रवासी कितने मजबूत हैं और वे अपनी जड़ों से कितने जुड़े हुए हैं।

देश के बाहर भी यूपीआई का प्रभाव बढ़ा वैश्विक साझेदारियों से मिला नया विस्तार

एजेसी ►► नई दिल्ली

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने उद्योगकर्ता अनुभव बढ़ाने के लिए यूपीआई में नई सुविधाएं शुरू की हैं। इसमें क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स, लोन और इश्योरेंस सेवाओं के एकीकरण और अन्य अनेक सुविधाएं शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की 3-4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान यूपीआई की अंतरराष्ट्रीय पहुंच का नया उदाहरण देखने को मिला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में गहरी रुचि व्यक्त की।

जून में हुए 24 लाख करोड़ मूल्य के लेनदेन

घरेलू स्तर पर भी यूपीआई लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अकेले जून 2025 में यूपीआई के जरिए 24,03,930 करोड़ रुपए मूल्य के लेनदेन दर्ज किए गए। यह वृद्धि साल-दर-साल प्रतिशत में नहीं बल्कि कई गुना मापी जा रही है। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अनुमान है कि जुलाई 2025 में यूपीआई लेनदेन का मूल्य 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जिसकी संभावना 80% आंकी गई है। वहीं, एनपीसीआई की वेबसाइट के मुताबिक, 7 जुलाई तक यह आंकड़ा 6,60,102 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।

साइप्रस ने सहमति जताई

इसके अलावा, जून 2025 में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान एनपीसीआई और यूरोबैंक साइप्रस ने दोनों देशों के बीच सीमा पार भुगतान के लिए यूपीआई शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसका उद्देश्य उनके आर्थिक संबंधों को मजबूत करना था।

अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज विमान जांच ब्यूरो ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट

एजेसी ►► नई दिल्ली

अहमदाबाद में 12 जून को हुए एअर इंडिया विमान हादसे की जांच तेज हो गई है। हादसे की जांच कर रही विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एआईबी) की टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को सौंप दी है। एआईबी 171 विमान दुर्घटना पर तैयार की गई रिपोर्ट जांच के शुरुआती निष्कर्षों पर आधारित है। एआईबी ने जांच के लिए बहु-विषयक टीम का गठन किया है। अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार गठित टीम का नेतृत्व डीजी एएआईबी कर रहे हैं। इस मामले में ब्लैक बॉक्स और हैंडलिंग कॉर्पाइट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) दोनों को बरामद कर लिया गया है।



के अनुसार गठित टीम का नेतृत्व डीजी एएआईबी कर रहे हैं। इस मामले में ब्लैक बॉक्स और हैंडलिंग कॉर्पाइट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) दोनों को बरामद कर लिया गया है।

इंटरनेशनल एजेसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर का दावा वर्ष 2008 से 2017 के बीच जन्मे डेढ़ करोड़ लोगों में पेट कैंसर का खतरा

एजेसी ►► कोलकाता

नई दिल्ली (भाषा)। दुनियाभर में वर्ष 2008 से 2017 के बीच जन्मे डेढ़ करोड़ से अधिक लोग जीवन में कभी न कभी पेट के कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं और ऐसे लोगों की सर्वाधिक संख्या चीन के बाद भारत में होगी। एक शोध रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन अनुमानित डेढ़ करोड़ कैंसर मरीजों में से दो-तिहाई लोग एशियाई देशों के हो सकते हैं, जबकि इसके बाद अमेरिका और

पश्चिम बंगाल एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई पाक आईएसआई से जुड़े दो लोग गिरफ्तार, 7 दिन पुलिस रिमांड पर

एजेसी ►► कोलकाता

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले से दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से संबंध होने का संदेह है। राज्य विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों की पहचान कोलकाता के भवानीपुर निवासी राकेश कुमार गुप्ता और पानागढ़ निवासी मुकेश रजक के रूप में हुई है। अधिकारी ने कहा कि इन दोनों को पाकिस्तान की आईएसआई से

सुरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं जेनिफर पैरामारिबो

एजेसी ►► कोलकाता

दक्षिण अमेरिका के छोटे परंतु सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश सुरीनाम को उसकी पहली महिला राष्ट्रपति मिल गई है। 71 वर्षीय एनु भ वी चिकित्सक और सांसद जेनिफर गीरलिंग्स-साइमंस को बीते रविवार को संसद से दो-तिहाई बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रपति चुना गया। यह चुनाव मई में हुए आम चुनाव के बाद हुआ, जिसमें कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। गीरलिंग्स-साइमंस, जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख हैं, 16 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी।

विकसित गांवों और समृद्ध किसानों के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी : धर्मेन्द्र

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसवीपीयूटी), मंगलवार को मेठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब



और एग्रीटेक स्टार्टअप तथा टेक नो लॉ जी शोकेस का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी उपस्थित थे। इस अवसर पर

अरिदनी वैष्णव के पिता का जोधपुर में निधन

जयपुर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दारुलाल वैष्णव का मंगलवार को एम्स, जोधपुर में निधन हो गया। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उनका अंतिम संस्कार शाम को जोधपुर में किया गया। पिछले कुछ दिनों से दारुलाल वैष्णव गंभीर रूप से बीमार थे और एम्स जोधपुर में उनका इलाज चल रहा था।



अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उनका अंतिम संस्कार शाम को जोधपुर में किया गया। पिछले कुछ दिनों से दारुलाल वैष्णव गंभीर रूप से बीमार थे और एम्स जोधपुर में उनका इलाज चल रहा था।

सीडीएस जनरल चौहान और नौसेनाप्रमुख एडमिरल त्रिपाठी से की मुलाकात

7 से 9 जुलाई तक भारत की यात्रा पर यूएई की नौसेना के कमांडर

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

भारत और पाकिस्तान के बीच पश्चिमी सीमा पर जारी तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की नौसेना के कमांडर मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला अलरेमीथी 7 से 9 जुलाई तक भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सहयोग



और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना है। मंगलवार को मेजर जनरल अलरेमीथी ने राजधानी में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की।

Sirf Ek कप चाय, कब्ज़ को Tata Bye-Bye

पेट सफा

Laxative Green Tea

Issai

FSSAI NO. : 1092499000065

पेट सफा... तो हर रोग दफा

Good for Digestion

Helps Relieve Constipation

अगर आपका पेट भी सुबह पूरी तरह से साफ नहीं होता तो इससे छुटकारा अब बिल्कुल आसान है, रात को सोते समय 'पेट सफा' Laxative Green Tea का सिर्फ एक कप पीना है, और सुबह आपका पेट होगा, एक झटके में बिल्कुल साफ और Fresh.

Buy Now: [amazon](#) | [Flipkart](#) | [blinkit](#) | [1mg](#) | [bigbasket](#) | [snapdeal](#) | [JioMart](#)

Contact For Dealership
85588 07777 • dealership@divisa.in